



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 अक्टूबर, 2023

आश्विन 25, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 1406/77-3-2023-142(एम)-2019

लखनऊ, 17 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

प0आ0-500

चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 516/77-3-22-142(एम)-2019, दिनांक 11 मई, 2022 लोक प्रयोजनार्थ अर्थात् उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अपेक्षित जिला बांदा तहसील-सदर, बांदा के ग्राम जौरही रकबा 0.0600 कुल 0.0600 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी और अन्ततः दिनांक 11 मई, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। कलेक्टर बांदा को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धों के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर, बांदा की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करती हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन बांदा के कलक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेश देती हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। (जिला बांदा में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।)

अनुसूची-क

क्रम-संख्या	जिला	तहसील का नाम	परगना	गांव	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	बांदा	सदर बांदा	बांदा	जौरही	689	0.0600

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जिला	तहसील	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
बांदा	सदर बांदा	शून्य	शून्य	शून्य
(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है।)				

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल योजना कलक्टर, बांदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1406/LXXVII-3-2023-142(M)-2019, dated October 17, 2023 :

No. 1406/LXXVII-3-2023-142(M)-2019

Dated Lucknow, October 17, 2023

WHEREAS preliminary notification no. 516/LXXVII-3-22-142(M)-2019, dated May 11, 2022 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the "said Act"), in respect of total 0.0600 Hectares of land in Village-Jaurahi 0.0600 of Tehsils Sadar Banda, district Banda required for public purpose, namely, Bundelkhand Expressway Project through Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority and lastly published on May 11, 2022. The Collector, Banda was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project-affected families;

NOW, THEREFORE, after considering the report of the Collector, Banda submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of section 15 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the aforesaid Act that she is satisfied that the area of the land mentioned in Schedule-A below is needed for public purpose and no land in the Village, Pargana and District as given in Schedule-B has been identified for rehabilitation and resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the said Act to direct the Collector of Banda to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith. (No family is likely to be displaced due to land acquisition for Bundelkhand Expressway Project in district Banda. Hence there is no need for identification of any land for rehabilitation and resettlement and publication of summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme.)

SCHEDULE-A

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired (In Hectare)
1	2	3	4	5	6	7
1	Banda	Sadar Banda	Banda	Jaurahee	689	0.0600

SCHEDULE-B

(Land Identified marked as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Village	Plot no.	Area Earmarked for rehabilitation (In Hectare)
1	2	3	4	5
Banda	Sadar Banda	Nil	Nil	Nil
(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project)				

NOTE : A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Banda.

By order,
ANIL KUMAR SAGAR,
Pramukh Sachiv.